



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 536) पटना, बृहस्पतिवार, 7 जून 2018

सं० 08/आरोप-01-203/2014,सा०प्र०-5771

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

7 मई 2018

श्री शालिग्राम साह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1021/11 के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, काराकाट, रोहतास के पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास आवंटन में मार्गदर्शिका के उल्लंघन संबंधी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोपों की वृहद जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-14796 दिनांक 11.09.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री साह से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। तत्पश्चात आरोप जाँच प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त इन्दिरा आवास आवंटन में प्रतीक्षा सूची के क्रम का उल्लंघन करने संबंधी प्रमाणित आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक-7165 दिनांक 19.05.16 द्वारा श्री साह को निन्दन (आरोप वर्ष-2008-09 के प्रभाव से) एवं दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया गया। उक्त दंडादेश को निरस्त करने हेतु श्री साह ने अपना पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (पत्रांक-5821 दिनांक 08.07.16) समर्पित किया, जिसमें उन्होंने तत्समय अत्यधिक कार्य बोझ से ग्रस्त रहने तथा संसाधनों की कमी होने के कारण स्वयं के स्तर पर हुई स्वाभाविक पर्यवेक्षकीय भूल को क्षमा योग्य दर्शाते हुए बचाव प्रस्तुत किया। समीक्षोपरान्त इन्दिरा आवास आवंटन की मार्गदर्शिका एवं श्री साह के कृत्य के आलोक में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा संकल्प ज्ञापांक-12457 दिनांक 12.09.16 द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7165 दिनांक 19.05.16 द्वारा संसूचित दंड यथावत रखा गया।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री साह ने पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की। एतदसंबंधी सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-16709/16 में दिनांक 07.08.17 को पारित आदेश द्वारा विभागीय दंडादेश (संकल्प ज्ञापांक-7165 दिनांक 19.05.16) एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने संबंधी आदेश (संकल्प ज्ञापांक-12457 दिनांक 12.09.16) निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही वादी के सभी अनुषंगी लाभों के भुगतान का भी आदेश दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त रीट याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का अभिमत गठित हुआ। तत्पश्चात विधि विभाग के परामर्श के उपरान्त एल०पी०ए०सं०-1803/17 (ओथ सं०-13431 दिनांक 16.12.17) दायर हुआ। इसी बीच रीट याचिका के आदेश का अनुपालन नहीं होने के आधार पर श्री साह ने पटना उच्च न्यायालय में अवमाननावाद दायर कर दिया। विभाग की ओर से रीट याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध एल०पी०ए० दायर किये जाने संबंधी स्थिति के आलोक में ओथ सं०-4684 दिनांक 19.03.18 के माध्यम से अवमाननावाद

(एम०जे०सी०सं०-173/18) में कारण पृच्छा दायर किया गया। दिनांक 18.04.18 को सुनवाई के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

" This contempt application was filed on 17.01.2018 and was taken up on 14.03.2018 when as prayed, the learned State Counsel was allowed time to file show cause which is filed on behalf of the opposite party nos. 1 to 3 and it is hiding behind filing of LPA No.1803 of 2017, that they seek to avoid this proceeding. The show cause is rejected for a mere filing of Letters patent Appeal ipso-facto does not stay the operation of the judgment and order of the writ Court. I thus would give two weeks' further time to opposite party nos. 1 to 3 to provide consequential benefits to the petitioner or to obtain stay order on the pending appeal failing which this Court would proceed to frame charge against them.

Enabling the opposite parties to do the needful, put up this matter on 2nd of may, 2018.

इसी क्रम में अवमाननावाद से संबंधित अपर महाधिवक्ता सं०-03 द्वारा भी यथाशीघ्र मामले की सुनवाई होने की सम्भावना के आलोक में अग्रोत्तर कार्रवाई का निदेश दिया गया।

विभागीय स्तर पर मामले की गहन समीक्षा में यह पाया गया कि रीट याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध दायर एल०पी०ए०सं०-1803/11 में स्थगनादेश प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में अवमाननावाद में दिनांक 18.04.2018 को पारित अन्तरिम आदेश की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-16709/16 में दिनांक 07.08.2017 को पारित आदेश का अनुपालन अपरिहार्य है।

अतएव श्री शालिग्राम साह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1021/11 से संबंधित संकल्प ज्ञापांक-7165 दिनांक 19.05.2016 एवं संकल्प ज्ञापांक-12457 दिनांक 12.09.2016 (यथा क्रमशः दंडादेश एवं पुनर्विलोकन अस्वीकृति संबंधी आदेश) वापस लिया जाता है।

2. यह आदेश एल०पी०ए०सं०-1803/11 में पारित होने वाले न्यायादेश से प्रभावित होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 536-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>